(b) if so, how do they compare with those in the developed countries;

(c) the measures proposed for modernisation; and

(d) by when the modernisation programme will be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) Modernisation of rescue services in coal mines, undertaken in accordance with the modernisation plan drawn up in this regard, is expected to be completed by the end of 1998. The plan envisaging construction of new rescue stations and rescue rooms in different coalfields, provision of state-of-the-art rescue apparatus and equipment and also upgradation of the training standards for rescue brigades etc., compares favourably with those provided in the developed countries.

लघु उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि किया जाना

780. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार लघु औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा कितनी है और सरकार ने इसे किस सीमा तक बढ़ाना निर्धारित किया है;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में उल्लिखित मदों की वर्तमान संख्या को कम करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण के लिए आरक्षित मद-सूची से बाहर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) इस समय लघु उद्योग एकक के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रु० है। अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों/निर्यातोन्मुख लघु उद्योग एककों के लिए यह सीमा 75 लाख रु० है। सरकार, वर्तमान पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

(ग) से (ङ) इस समय, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या 836 है। लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

देश में बेरोजगारी

781. **श्री रामजीलाल:**
श्री जगन्नाथ सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुशल और अकुशल शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं; और

(ख) इस बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और वह सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा देगी?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) 31.12.1989 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुशल/अर्धकुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वाले यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हो, की संख्या क्रमशः 11.8 लाख तथा 49.3 लाख थी।

(ख) यद्यपि नई आर्थिक नीति के 1991 के प्रारम्भ से रोजगार चाहने वालों की संख्या में कोई दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी है। सरकार ने रोजगार सृजन को अपनी विकास योजनाओं हेतु किये जाने वाले प्रयासों के केन्द्र में रखा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों तथा सब-सैक्टरों यथा, कृषि, कृषि तथा ग्राम्य उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक तथा सेवा क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, पहले से चालू योजनाओं, यथा, आई आर डी पी, जे आर वाई तथा एन आर वाई के साथ-साथ नई रोजगार सृजन योजनाएं यथा, रोजगार आश्वासन योजना (इ ए एस), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर

वाई) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (के वी आई सी) की 20 लाख रोजगार अवसरों की योजनाएं आरम्भ की गई हैं। प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी निर्धनता उपशमन कार्यक्रम (आई यू पी ए पी) में रोजगार सृजन की समग्रता के साथ जनसंख्या के निर्धन वर्गों की मूल सेवाओं का प्रावधान इसकी एक आधारभूत विशेषता है।

Indo-Israel Chamber of Commerce

782. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether in a bid to boost the Indo-Israel trade a proposal to set up a Indo-Israel Chamber of Commerce at Hyderabad is being considered;

(b) if so, by when a final decision in this regard is likely to be taken;

(c) the total trade between the two countries at present;

(d) to what extent it will be improved; and

(e) whether Israel has already emerged as a major trading partner of India; and

(f) the areas in which India & Israel are improving the trade?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) There is no proposal at present with Ministry of Commerce to set up an Indo-Israel Chamber of Commerce at Hyderabad.

(c) The total trade between India and Israel during 1995-96 was Rs. 1506.52 crores.

(d) While it is not possible at this stage to make any accurate forecast about trade between India and Israel during 1996-97; it is expected to grow further.

(e) Israel's share in India's global trade during 1995-96 was about 0.7%.

(f) Our major exports to Israel are gems & jewellery, cotton and manmade textiles, cashew, coffee, organic/inorganic/basic chemicals, engineering goods, etc. Our main imports from Israel are fertilizers, pearls, precious and semi-precious stones, organic/inorganic chemicals, machinery, project goods, petroleum products, etc.

छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन एवं रिरोलिंग मिलें

783. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्पंज आयरन एवं रिरोलिंग मिल के कितने-कितने कारखाने कहां-कहां और कब से स्थापित हैं;

(ख) इन मिलों के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई थी और किस मूल्य पर प्रत्येक को उपलब्ध कराई गई थी;

(ग) इन स्थापित मिलों में से कौन-कौन सी मिलें कब से बंद कर दी गई है; और

(घ) इन मिलों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Construction of Tobacco Barns

784. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government will finance or subsidise the construction of tobacco barns in flood-affected areas of Andhra Pradesh;

(b) whether Tobacco Board surveyed the damage to tobacco barns in coastal Andhra due to recent cyclonic weather;

(c) if so, the details of the survey; and

(d) the steps proposed to assist the farming community by the Tobacco Board in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH) (a) Yes Sir, Tobacco Board is providing financial assistance to the SC/ST/Small and marginal farmers for repair/construction of